राज्य द्वारा कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन के दमन का विरोध करो !

वर्ष **2008** में भारत सरकार ने अपने एक मूल्यांकन को बदल दिया। उसने कहना शुरू किया कि 'माओवाद' मुल्क की सबसे बड़ी चुनौती है। माओवादी आंदोलन को नेस्तनाबूद करना सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है। कश्मीर या उत्तर–पूर्व के आंदोलन (राष्ट्रीय मुक्ति) को अब तक सबसे बड़ी चुनौती मानकर उससे निपटने के इंतजामों में मसरूफ भारतीय राजसत्ता अचानक ऐसा क्यों करने लगी?

माओवाद को राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती घोषित करने वाले प्रधानमंत्री के बयानों से गृहमंत्री ने अपनी नाइत्तेफाकी जतलायी। जरखरीद बुद्विजीवियों के बीच सरकार की इस घोषणा को लेकर परस्पर विरोधी अवस्थितियां बनीं रहीं, हालांकि इस पर कोई भी मतभेद नहीं है कि 'माओवादी' आदोलन का निर्मम दमन किया जाये। सरकार जब 'माओवादी' कहती है तो उसका आशय स्पष्ट है। हाल–फिलहाल यह भाकपा (माओवादी) की बात करती है। फिर भी आज चाहे सरकार जो भी कह रही हो उसके 'माओवादी' शब्द की व्याख्याओं का विस्तार किया जा सकता है और किया जाएगा।

खैर... सरकार की इस घोषणा को लेकर खुद सरकार से लेकर बुद्विजीवियों तक के बीच मौजूदा अंतर्विरोध की वजह है। 'माओवादी' आंदोलन की वजह से हुयी 'हत्याओं' का आंकड़ा कम से कम कश्मीरी मुक्ति संघर्ष तथा उत्तर–पूर्व में हुयी 'हत्याओं' से काफी कम है। चाहे हत्याएं आंदोलनकारियों की हों, सरकारी मुलाजिमों की या आम जनता की। इसीलिए यह सरकारी घोषणा और इसकी आड़ में किया जा रहा दमनचक्र सभी को बदहजमी पैदा कर रहा है। फिर भी सरकार इसे हजम करवाना चाहती है तो उसके कई कारण है।

इनमें पहला कारण है सरकार की नीतियों विशेषकर उदारीकरण, वैश्वीकरण, के बाद पैदा हुयी भयावह सामाजिक स्थिति। जनता के लगातार बदतर होते जा रहे हालातों के बीच से आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक ही है। इन हालातों में भारत का कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन ही वह ताकत बनता है जो जनता को व्यवस्था विरोधी अवस्थितियों पर खड़ा कर रहा है। सरकार जानती है कि वैश्वीकरण की नीतियों के परिणाम आ रहे हैं और आयेंगे। एक ओर जहां अमीर गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जायेगी वहीं बदहाल आम जनता भी चुप नहीं बैठेगी। इसके संकेत विभिन्न आयामों से आ रहे हैं।

जनता का यह आक्रोश राष्ट्रीयता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता इत्यादि में अभिव्यक्त पाए इससे सरकार को, पूंजीपति वर्ग को कोई खास दिक्कत नहीं है। पूंजीपति वर्ग की दिक्कत यह है कि यह आक्रोश एकताबद्व होकर मालेमा विचारधारा के निर्देशन में संगठित हो सकता है। इसीलिए सरकार पहले ही माओवाद का हव्वा खड़ा कर उससे निपटने के साथ–साथ जनता के बीच विचारधारा के प्रति डर–भय का वातावरण भी बना रही है। साम्राज्यवादी तथा पूंजीपति वर्ग के बीच मालेमा विचारधारा के स्थापित हो जाने का भय इस कदर है कि नेपाल में इसके उभार से भी इनके पेट में मरोड़ उठने लगती है। भारत में कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन की एक शारदार विरासत है। इसका वर्तमान भी अच्छा है, टूट–फूट, बिखराव के बावजूद। भविष्य, एक शानदार भविष्य इसका इंतजार कर रहा है। हम इस भविष्य के प्रति आशान्वित हैं और शासक वर्ग आतंकित। इसी का नतीजा है, हमें चुनौती के तौर पर प्रस्तुत करना व भयानक दमनचक्र।

इस दमनचक्र का निशाना सभी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी संगठनों को बनाया जा रहा है मगर विभिन्न रूपों में। किन्हीं संगठनों के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्याएं तक की जा रही हैं, किन्हीं संगठनों के कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर उन्हें डराया–धमकाया जा रहा है। इस दमनचक्र का निशाना क्रांति में सच्ची आस्था रखने वाले ही हैं। माओ के विचारों को मानने का इससे कोई भी लेना–देना नहीं है। सी.पी.आई.एम.एल. (लिबरेशन) को बिहार राज्य चुनाव आयोग बकायदा मान्यता दे चुका है। जबकि लिबरेशन भी माओ विचारधारा को मानने तथा सशस्त्र संघर्ष द्वारा व्यवस्था परिवर्तन की किताबी बातें घोषित तौर पर स्वीकारता है।

बात बातों से तय नहीं होती है व्यवहार से होती है। सरकार अपना दमनचक्र लगातार तेज कर रही है। कहीं सलवा जुडूम तो कहीं स्पेशल टास्क फोर्स तो कहीं कुछ और इस दमनचक्र रूपी दशानन के सर हैं। भारतीय पूंजीपति वर्ग के इस निर्मम दमन में कई कामरेड साहसपूर्वक शहीद हो गए हैं और कई जेलों में बंद हैं।

हम सरकार के माओवाद विरोधी अभियान में शहीद हुए कामरेडों को अपनी दिली भावनाओं के साथ लाल सलाम पेश करते हैं और उनकी याद में लाल परचम् झुकाते हुए उनके संकल्पों को अंगीकार करते हैं।

हम जानते हैं कि लाख प्रयासों के बावजूद सर्वहारा क्रांति की विजय सुनिश्चित है। इसी बात से साम्राज्यवादी, पूंजीवाद भय खाते हैं और हमें कुचलना चाहते हैं। इसी से हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं।

....